

Selection Scale to Teachers

2908. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a proposal to grant Selection Scale to Government School including Kendriya Vidyalaya teachers after they put in 18 years' continuous service in a cadre is under Government's consideration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is likely to be effected?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) There is no proposal under consideration of Government to grant Selection Scale in Govt. schools including Kendriya Vidyalaya teachers who have rendered 18 years' continuous service in a cadre. However, the revision of pay scales of school teachers approved by Govt. of India in August 1987 provides for Selection grade to teachers who have completed 12 years service in the senior scale, subject to fulfilment of other conditions.

(c) Does not arise.

औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास के लिए साक्षरता का होना अनिवार्य

2909. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

श्री राम जेठमलानी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1992 के "दि इकोनॉमिक टाइम्स" में "टाइगर्स नीड मीट" नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि औद्योगिकीय तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में शक्तिशाली बन के लिए देश के लिए कम से कम 80 प्रतिशत साक्षर हासिल करना जरूरी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की कौशल प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) "टाइगर्स नीड मीट" नामक शीर्षक अंतर्गत प्रकाशित समाचार दिनांक 22 नवम्बर, 1992 "दि इकोनॉमिक टाइम्स" (न्यू दिल्ली एडिशन) प्रकाशित हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) और (ग) सूचना, सम्प्रेषण तथा कौशल अत्यधिक विस्तृत संसार की समझ तथा जागृति के लिए साक्षरता को एक प्रवेश बिन्दु माना गया है तथा विकास तथा राष्ट्रीय विकास के लिए एक पूर्व-प्रतिवर्धन भी समझा गया है। यदि चहुं और निरक्षरता फैली हुई तो ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति, कुछ हद तक सीमित हो जाएगी अथवा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों के लाभों को पूरी तरह से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक शोध को व्यावहारिक बनाने के विचार साक्षरता (शिक्षा) की प्रगति को राष्ट्रीय मिशनों में एक माना गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो 1988 में शुरू किया गया था, का मुख्य लक्ष्य, 1995 तक 15 से 35 आयु-वर्ग में 80 मिलियन निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। साक्षरता अभियान, जो इस मिशन की मुख्य नीति देशभर के 179 जिलों में आंशिक या पूर्ण रूप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना अंत तक पूर्ण साक्षरता अभियानों में 345 जिलों शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि साक्षरता दर 70% लगभग बढ़ जाए क्योंकि इस स्तर को अनुवर्ती वर्ष पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण समझा है।